



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 248]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 3, 2018/आषाढ़ 12, 1940

No. 248]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2018/ASHADHA 12, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2018

सं. टीएएमपी/46/2018-एमयूसी.—पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, के 06 जून, 2018 के पत्र संख्या पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार सभी महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालन कर रहे सभी वीओटी प्रचालकों के दरमानों में अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की उगाही के लिए उपबंध अंतर्विष्ट करते हुए एक कॉमन आदेश अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या. टीएएमपी/46/2018-एमयूसी

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जून, 2018 के 8वें दिन पारित)

पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने 06 जून, 2018 के पत्र संख्या पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के द्वारा इस प्राधिकरण को सभी महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित टर्मिनलों के दरमानों में सभी कंटेनरों पर वर्ष 2018-19 के लिए दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) द्वारा प्रदान की जाने वाली संभरण डाटा बैंक सेवा

के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के समान अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की उगाही का उपबंध व्यवस्थित करने संबंधी कॉमन आदेश जारी करने की संसूचना दी है।

2.1. इस संबंध में, यह कहना है कि भारत सरकार वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर (डीएमआईसी) विकसित कर रही है और डीएमआईसी परियोजना के कार्यक्रम प्रबंधन तथा विकास के लिए दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर विकास निगम (डीएमआईसीडीसी) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) निगमित किया गया है। इस बारे में, कंटेनरों का सभी पत्तनों से आईसीडीएस और अन्तिम प्रयोक्ता तक खोज रखने के लिए, डीएमआईसीडीसी ने एक ही गवाक्ष के भीतर विस्तृत वास्तविक समयपरक सूचना प्रदान करने के लिए संभरण डाटा बैंक (एलडीबी) का विकास किया है जो संपूर्ण आपूर्ति चेन में विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध सूचना को एकीकृत करेगा। परियोजना की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में कंटेनर की आवाजाही की निकटवर्ती वास्तविक समयक सूचना उपलब्ध कराने की मंशा है और इस प्रकार, कंटेनर संभरण आवाजाही को सरल और कारगर बनाना है।

2.2. तदनुसार, प्राधिकरण ने 13 फरवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी के द्वारा जेएनपीटी पर और जेएनपीटी पर अन्य बीओटी टर्मिनलों नामतः न्हावा शेवा इंटरनैशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एनएसआईसीटीएल), और गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) पर प्रहस्त होने वाले कंटेनरों पर (पोतांतरण और तटीय के सिवाय) वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) की उगाही के जेएनपीटी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमोदित एमयूसी की दर 145/- रु. प्रति कंटेनर है।

3.1. अब, सभी महापत्तन न्यासों और वहां प्रचालित निजी टर्मिनलों पर लागू जेएनपीटी के समान एमयूसी की उगाही के लिए एमओएस से इस प्राधिकरण को प्राप्त कॉमन आदेश पारित करने की सूचना के आधार पर, यह प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनलों के दरमानों में एमयूसी की उगाही से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट करने को सहमत है, जैसा 13 फरवरी 2015 के आदेश में अनुमोदित किया गया है।

3.2. महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनलों द्वारा एमयूसी की वसूली डीएमआईसीडीसी द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं/सुविधाओं के लिए है। इस प्रकार, पत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनल एमयूसी का संग्रहण करेंगे और उसे डीएमआईसीडीसी को प्रेषित करेंगे। दूसरे शब्दों में, महापत्तन न्यास और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनल डीएमआईसीडीसी की ओर से संग्रहण एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। इस प्रकार एमयूसी की उगाही से महापत्तनों और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनलों को कोई अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति नहीं होगी और न ही उन्हें लाभप्रद स्थिति में समझा जायेगा। यह भी कि, इस संबंध में प्राइवेट टर्मिनलों द्वारा कोई राजस्व सृजित नहीं किया जा रहा है, इसलिए उन्हें इस मद पर संबंधित स्वामी पत्तन को कोई रायल्टी/राजस्व नहीं देना होगा। उक्त स्थिति को देखते हुए सभी महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनलों के प्रशुल्क निर्धारण के लिये, एमयूसी की उगाही करने के एमओएस से प्राप्त उक्त संसूचना के आधार पर, एमयूसी की उगाही करना वर्ष 2005, 2008 और 2013 के दिशानिर्देशों द्वारा शासित सभी महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित निजी टर्मिनलों पर लागू किया जाता है। कुल एमयूसी का 5% महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित बीओटी टर्मिनलों को एमयूसी संग्रहण के लिये दिया जायेगा, जैसा कि 13 फरवरी 2015 के जेएनपीटी के आदेश के पैरा 6(ix)(क) में अभिलेखबद्ध किया गया है।

3.3. पूरी सावधानी के तौर पर, यह नोट किया जाये कि 2008 और 2013 के दिशानिर्देशों द्वारा शासित निजी टर्मिनलों के लिए एमयूसी प्रभार के निर्धारण को 2008 और 2013 के दिशानिर्देशों द्वारा शासित निजी टर्मिनलों के अन्य किन्हीं प्रभारों के निर्धारण के लिए पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धरित नहीं किया जायेगा।

3.4. जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के लिए एमयूसी प्रभार इस प्राधिकरण के 13 फरवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी के द्वारा पहले ही अनुमोदित किया गया है। अतः एमयूसी प्रभार, जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के सिवाय, सभी महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित बीओटी टर्मिनलों के लिए अनुमोदित किया जाता है।

4.1. तदनुसार, यह प्राधिकरण सभी महापत्तन न्यासों और उनमें प्रचलित बीओटी टर्मिनलों को, जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के सिवाय, निदेश देता है कि वे अपने संबंधित दरमानों में निम्नलिखित प्रावधान अंतर्विष्ट करें:—

“महापत्तन न्यास और वहां प्रचलित टर्मिनल पर प्रहस्तित सभी कंटेनरों (सिवाए पोतांतरण और तटीय के) पर 145/- रु. प्रति कंटेनर की राशि की उगाही डीएमआईसीडीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली संभरण डाटा बैंक (एलडीबी) सेवा के लिए अनिवार्य प्रयोक्ता प्रभार (एमयूसी) के रूप में की जाएगी।”

- 4.2. 145/- रु. प्रति कंटेनर की एमयूसी अधिकतम स्तर हैं। महापत्तन न्यास या वहां प्रचालित निजी टर्मिनल डीएमआईसीडीसी के साथ परामर्श करके कम दर पर प्रभारों की उगाही को स्वतंत्र हैं।
- 4.3. सभी पत्तनों में कंटेनरों की आवाजाही को आईसीडीएस और अंतिम प्रयोक्ता को खोजना और देखना एमयूसी के भुगतान के प्रति प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4.4. कुल एमयूसी का 5% महापत्तन न्यासों और उन पर प्रचालित बीओटी टर्मिनलों को एमयूसी संग्रहण के लिये दिया जायेगा।
- 4.5. बीओटी टर्मिनलों को एमयूसी संग्रहण के लिये महापत्तन न्यासों में प्रचालित बीओटी टर्मिनलों को संबंधित स्वामी पत्तन को कोई रायल्टी/राजस्व नहीं देना होगा।
- 4.6. पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने अपने 06 जून, 2018 के पत्र संख्या पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के द्वारा सभी महापत्तन न्यासों को एमयूसी की उगाही के उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करने और 01 अप्रैल, 2019 से प्रभावी होने वाले एमयूसी के अनुमोदन के लिये इस अधिकरण के समक्ष प्रस्ताव दायर करने में डीएमआईसीडीसी से समन्वय करने का अनुरोध किया है। इसलिये, इस आदेश में अनुमोदित एमयूसी पारित आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और 31 मार्च 2019 तक वैध रहेगा। दिया गया अनुमोदन स्वतः व्यपगत हो जायेगा जब तक कि प्राधिकरण द्वारा इसका विशिष्ट रूप से विस्तार नहीं कर दिया जाता।
5. एमयूसी के और ब्यौरे और एलडीबी परियोजना के कार्य-प्रवाह के लिये 13 फरवरी, 2015 का आदेश संख्या टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी देखा जा सकता है।
6. सभी महापत्तन न्यासों और उनमें प्रचालित टर्मिनलों को, जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के सिवाए, अपने दरमानों में संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा. /125/18-19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June, 2018

No. TAMP/46/2018-MUC.—In pursuance to the Ministry of Shipping, Government of India, communication vide letter No. PD-14033/34/2017-PD-V, dated 06 June 2018 and in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies a Common Order incorporating a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/46/2018-MUC.

QUORUM

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of June, 2018)

The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. PD-14033/34/2017-PD-V dated 06 June 2018 has conveyed to this Authority to issue a common Order applicable to all the Major Port Trusts and the terminals operating thereat, to prescribe a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers towards the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC), in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and terminals operating thereat for the year 2018-19 at par with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1. In this regard it is to state that the Government of India is developing the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) as a global manufacturing and investment destination and has incorporated a special propose Vehicle (SPV) namely the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) for program managing the development of the DMIC Project. In this connection, to keep a track on the movement of containers across the ports to the ICDs and the end users, the DMICDC has developed the Logistic Data Bank (LDB) to integrate the information available with various agencies across the supply chain to provide detailed real time information within a single window. The project is intended to provide the near real time visibility of the container movement across the supply chain, thereby streamlining the container logistic movement.

2.2. Accordingly, this Authority vide its Order no. TAMP/49/2014-JNPT, dated 13 February 2015 has approved the proposal of the JNPT to levy the Mandatory User Charge (MUC) on containers (except transshipment and coastal) handled at JNPT and at other BOT Terminals at JNPT viz., Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL) and Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) for the years 2016-17 to 2018-19. The rate of MUC approved for the year 2018-19 is ₹ 145/- per container.

3.1. Now, based on the communication received from the MOS to this Authority to pass a common Order for levy of MUC applicable to all the Major Port Trusts and private terminals operating thereat at par with JNPT, this Authority agrees to incorporate the provision relating to levy of MUC in the Scale of Rates of all Major Port Trusts and private terminals operating thereat, as approved in the Order dated 13 February 2015.

3.2. The collection of the MUC by the Major Port Trusts and private terminals operating thereat is for the service/facilities made available by the DMICDC. Thus, the Major Port Trusts and private terminals operating thereat would only be collecting the MUC and remitting the same to DMICDC. In other words, the Major Port Trusts and private terminals operating thereat would only be acting as the collection agents on behalf of the DMICDC. Thus, levy of MUC shall not result in additional revenue to the Major Port Trusts and private terminals operating thereat and shall not put them in an advantageous position. Also, since no revenue is being generated on this account to the private terminals, no royalty/revenue share shall be payable by the private terminals to their respective landlord Ports, on this item. In view of the above position and based on the communication received from the MOS to make the levy of MUC applicable to all the Major Port Trusts and private terminals operating thereat, the levy of MUC is made applicable to all the Major Port Trusts and to all the private terminals operating thereat governed by 2005, 2008 and 2013 Guidelines for fixation of tariff. 5% of the total MUC shall be passed on to the Major Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat for collecting the MUC, as recorded in the JNPT Order dated 13 February 2015 vide paragraph No. 6 (ix) (a).

3.3. As a measure of abundant caution it may be noted that the prescription of MUC charge for the private terminals governed by 2008 and 2013 Guidelines shall not be quoted as a precedent for prescription of any other charges for the private terminals governed by 2008 and 2013 Guidelines.

3.4. The MUC Charge has already been approved for JNPT, NSICTPL and GTIPL vide Order No. TAMP/49/2014-JNPT dated 13 February 2015. Hence the MUC Charge is approved for all Major Port Trusts and BOT Terminal Operators operating thereat except JNPT, NSICTPL and GTIPL.

4.1. Accordingly, this Authority directs all the Major Port Trusts and the BOT terminals operating thereat except JNPT, NSICTPL and GTIPL to incorporate the following provision in their respective Scale of Rates:—

“An amount of ₹ 145/- per container will be levied on all containers (except transshipment and coastal) handled at the Major Port Trusts and terminals operating thereat towards Mandatory User Charge (MUC) for the Logistics Data Bank (LDB) service to be rendered by DMICDC.”

- 4.2. The MUC of ₹ 145/- per container prescribed is at ceiling level. The Major Port Trusts and the private terminals operating thereat have the liberty to charge lower rates in consultation with DMICDC.
- 4.3. Tracking and viewing the movement of containers across the ports to the ICDs and end users would be provided to the users against the payment of MUC.
- 4.4. 5% of the total MUC shall be passed on to the Major Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat for collecting the MUC.
- 4.5. No royalty/ revenue share is payable by the BOT Terminals operating thereat to the Port Trusts on the MUC collected by the BOT Terminals.
- 4.6. The MOS vide its letter No. PD-14033/34/2017-PD-V, dated 06 June 2018 has already requested all the Major Port Trusts to coordinate with DMICDC to formulate a suitable proposal for levy of MUC and file the proposal before this Authority for approval of MUC with effect from 01 April 2019. Therefore, the MUC approved in this Order shall come into effect from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India and shall remain valid till 31 March 2019. The approval accorded shall automatically lapse unless until specifically extended by this Authority.
5. For further details on the MUC and workflow of LDB Project, the Order No. TAMP/49/2014-JNPT, dated 13 February 2015 may be referred to.
6. All the Major Port Trusts and the terminals operating thereat except JNPT, NSICTPL and GTIPL are directed to amend their Scale of Rates accordingly.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty. /125/18-19]